Paper IV

Ques. भारत में सार्वजनिक उद्योगों की मूल्य नीति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए।

B.A. II Hons

Dr Kumari Manju
P.G.D.
Eco

(What do you understand by Public Enterprises? Ans, What should be the Price Policy of Public Enterprises in India.)

Ans;

लोक उद्योगों की मूल्य नीति निजी उद्योगों की मूल्य नीति से भिन्न होती है। निजी उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत एक ओर सीमान्त क्रेता को वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करती है तो दूसरी ओर वह उत्पादक को उत्पादन से प्राप्त लाभ तथा औसत लागत है। लोक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु के क्रेता निजी वस्तु के क्रेता से भिन्न नहीं हैं। क्रेता को वस्तु की उपयोगिता खरीदने के लिए कीमत चुकाना है। यदि कीमत उपयोगिता के अनुकूल नहीं है तो वह नहीं खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्ति के पक्ष में स्थिति बिल्कुल अलग है। दीर्घकाल में नीजि निजी वस्तु की कीमत को कम-से-कम कुल लागत के समान होना होगा, साथ ही इतना लाभ मिलना चाहिए कि व्यावसायिक उद्योग के लिए पूँजी उपलब्ध हो जाए। सरकार ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित नहीं होती है। चूँकि सरकार सामान्य कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रेरित होती है, अतः इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत केवल वाणिज्य के सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित नहीं होती है। सरकार द्वारा निर्धारित कीमत प्रतिस्पर्धी निजी फर्म द्वारा निर्धारित कीमत से भिन्न हो सकती है। यही कारण है कि लोक उद्योगों की मूल्य नीति का विश्लेषण करना चाहिए। मूल्य नीति के सम्बन्ध में अक्सर निम्न सिद्धान्तों की चर्चा की जाती है—

(1) सीमान्त लागत पर आधारित कीमत निर्धारण (Marginal Cost pricing);

(2) न लाभ न हानि का सिद्धान्त (Principle of Break-even, that is no Profit, no loss;).

(3) औसत लागत पर आधारित कीमत निर्धारण (Average Cost

Scanned with CamScanner

Pricing); तथा

(भ) लाभ प्राप्त करने का सिद्धान्त (Principle of making profits.);

<u>विशेषताएँ</u>: (1) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग — देश के सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों का संचालन प्राचीन काल से ही सरकारी नियंत्रण में होता आया है। राष्ट्र की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों का संचालन सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त समझा जाता है। कोई भी सरकार युद्ध-सामग्री, जैसे वायुयान, जलयान व अस्त्र-शस्त्र आदि के लिए व्यक्तिगत उद्योगों पर निर्भर नहीं रह सकती है।

(2) प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा — देश के खनिज, वन आदि प्राकृतिक साधनों के उपयोग में भी सरकारी नियंत्रण को उचित समझा जाता है। प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, परन्तु बुद्धिमानी इस बात में है कि उनका उपयोग मितव्ययितापूर्वक हो। यदि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व दे दिया जाय तो वे लाभ-भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे।

(3) एकाधिकारी उद्योग — ऐसे उद्योगों पर नियंत्रण सरकार द्वारा होनी चाहिए। एकाधिकारी शक्तियों के कारण देश में आर्थिक एवं सामाजिक बुराई उत्पन्न होती है। एकाधिकारी का उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना तथा वस्तुओं का अभाव पैदा करना। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर ले।

(4) जन कल्याण — जन कल्याण की भावना तभी आ सकती है जब उत्पादन का कार्य सार्वजनिक संस्थाओं को सौंपा जाय।

(5) आधारभूत उद्योग — प्रत्येक देश में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अर्थव्यवस्था का मूलाधार होते हैं। इन उद्योगों को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, बिजली, रेलवे, लोहा इस्पात तथा खाद के बड़े कारखाने आदि। अतः ऐसे उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में होना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

(6) एकीकृत संचालन की क्रियाएँ — सरकारी उद्योगों के पक्ष में यह कहा जाता है कि कुछ क्रियाएँ इस किस्म की होती हैं जिनमें प्रतियोगिता से फिजूलखर्ची बढ़ती है, उदाहरणस्वरूप नगर में जल-कल की व्यवस्था, सड़क यातायात तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था।

(7) धन के केन्द्रीकरण पर रोक — पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली की यह विशेषता है कि प्रतियोगिता के कारण धन कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाता है, यह विषम आर्थिक असमानता को जन्म देते जाते हैं, धनी बनते जाते हैं और निर्धन दिन-प्रतिदिन निर्धन होता जाता है, यदि उद्योग धन्धों का संचालन ~~स्वयं~~ स्वयं सरकार करे तो धन का समान वितरण होगा और गिने-चुने व्यक्तियों का एकाधिकार समाप्त हो जायेगा।

(8) विकासशील देशों में सरकारी उद्योग — सरकारी उद्योग के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए सरकारी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, इन देशों में आय, बचत तथा विनियोग की मात्रा कम होने से व्यक्तिगत उद्यमी आर्थिक तथा औद्योगिक विकास जैसे कठिन कार्य को पर्याप्त मात्रा में अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों में लागत अधिक आती है जबकि लाभ कम होता है, विकासशील देशों का अनुभव यही बताता है कि चाहे वे देश समाजवादी हो या पूँजीवादी वहीं सरकारी उद्योग आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जैसे —

(a) यातायात विद्युत तथा ~~मूलभूत~~ अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कार्य सरकार अर्थव्यवस्था का विकास कर सकती है।

(b) सरकारी उद्योग विकास गति का निर्धारण करते हैं, क्योंकि विकासशील देशों में कुशल साहसियों की कमी होती है, फलत: सरकारी उद्योग सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, इस राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाते हैं।

Scanned with CamScanner